

Ministry so that people know what is happening in this country and what precaution we can take for future to prevent occurrence of such tragedies and accidents. I hope the Government will react. Hon. Parliamentary Affairs Minister is here. Madam, let him say something on this.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): मैडम, मैं ... (ध्वनिघटन)...

उपसभापति: मल्होत्रा जी, एक मिनट देखिए, यह मैटर सिर्फ अमरनाथ यात्रा का नहीं है, यह मैटर उसके विषय में जरूर उठाया गया है लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जब मैम्बर के दबाव से, उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर The Government constitute an inquiry committee. Then Members keep quiet thinking that the Government is taking care of it. Afterwards the Members are not informed what happened. Members have a right to know what happened. So the Parliamentary Affairs Minister should please make a note of it; otherwise, we will make it compulsory and it should be made compulsory that every committee which is constituted on the request and demand of the Members of Parliament, the Government should lay the report of the that committee before the House, and if necessary, we can go through it. I am not suggesting that it should go to the Standing Committee. That is the decision of the Chairman and the Speaker in the other House. But at least the Members have a right to know what has been done in that matter. Otherwise, the accountability of the Members is at stake and the accountability of the Government is at stake. Chaudhari Chunni Lal.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, यह कमेटी...

उपसभापति: अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यात्रा के सिलसिले में क्योंकि वह बात हो चुकी है।

RE: SALE OF ANPARA THERMAL UNITS TO A SOUTH KOREAN COMPANY

चौधरी चुन्नीलाल (उत्तर प्रदेश): मैं इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा सदन और आपको ध्यान सरकार के एक अनैतिक कार्य की ओर दिला रहा हूँ जिससे विदेशी

कंपनियों की घुसपैठ होगी और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों की खेती और उपज पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

महोदया, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का प्रसिद्ध ताप बिजलीघर अनपरा, भारत सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में है और वह किसानों को 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति करता है। लेकिन अनेक सूत्रों से ऐसा पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बिजलीघर को निजीकरण के बहाने एक विदेशी कंपनी "हुपडई" जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसे बेच रही है जो कि किसानों को 3 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति करेगी। महोदया, यह आजकल की दर से कई गुना अधिक है। महोदया, किसान इस भार को वहन नहीं कर पाएगा और उसकी रीढ़ टूट जाएगी और उपज भी बहुत कम होगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस बिजलीघर को विदेशी कंपनी के हाथ में जाने से रोके और बिजली की दर बढ़ाने से रोके। धन्यवाद।

RE: NON-PAYMENT OF WAGES AND SALARIES TO IDPL WORKERS AND EMPLOYEES

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important issue. The IDPL management has issued directions for stopping payment of wages to the workers. About ten thousand workers were not paid their salaries for the last month and I am told that they are not going to be paid even for this month.

This company was started by the Government to achieve self-reliance in the field of drugs and pharmaceuticals. The company has nearly achieved this goal. It has produced various medicines at affordable prices. Almost all the basic drugs are being manufactured by this